

मुकदमों का विवरण

पंजाब राज्य और अन्य बनाम।

जसवंत सिंह

(सिविल अपील सं. 2014 की 11871) सितंबर 05, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण से लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवीक्षाधीन कांस्टेबल के निर्वहन आदेश के औचित्य के संबंध में मुद्दा उठा।

सेवा कानून-पंजाब पुलिस नियम, 1934 -आर. 12.21-परिवीक्षाधीन कांस्टेबल यू/आर का निर्वहन आदेश। 12.21 बिना किसी सूचना के लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा -

आयोजित किया गया: आर से यह स्पष्ट है। 12.21 कि यदि किसी परिवीक्षाधीन सिपाही के प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित होने की संभावना नहीं पाई जाती है, तो उसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-एस. एस. पी. द्वारा नामांकन की तारीख से तीन साल के भीतर किसी भी समय आरोपमुक्त किया जा सकता है-तथ्यों पर, बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण से लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण पर्यवेक्षी प्राधिकरण की सिफारिश पर आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया गया था-प्राधिकरण ने पाया कि परिवीक्षाधीन सिपाही को प्रशिक्षण में कोई रुचि नहीं है, और जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है, इस प्रकार, वह खुद को एक अच्छा, प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित नहीं कर सकता है-तीनों अदालतों ने आर. 12.21 और परिवीक्षाधीन के नेतृत्व में मुकदमे का फैसला सुनाया-आरोपमुक्त करने के आदेश की सामग्री को देखते हुए, आदेश में कथित कदाचार का कोई आधार नहीं है और यह एक परिवीक्षाधीन कांस्टेबल के सरल निर्वहन का आदेश है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय और दो अदालतों द्वारा भी लिया गया दृष्टिकोण कि परिवीक्षाधीन कांस्टेबल का निर्वहन अवैध था, कानून में गलत है और निर्धारित किया गया है। [पैरा 18-21]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

रत्नेश कुमार चौधरी बनाम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान

विज्ञान, पटना, बिहार और अन्य (2015) 15 एस. सी. सी. 151: [2015] 10 एससीआर 717-प्रतिष्ठित।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जसवंत सिंह 824

पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुखविंदर सिंह (2005) 5 एससीसी 569:[2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 580; पंजाब राज्य और अन्य बनाम सिपाही अवतार सिंह (2008) 7 एस. सी. सी. 405; अमर कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2013) 4 पी. एल. जे. आर. 269; शेर सिंह, पूर्व-सिपाही बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। 1994 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 166; पुलिस अधीक्षक बनाम द्वारका दास (1979) 3 एस. सी. सी. 789:[1979] 2 एस. सी. आर. 405; पंजाब राज्य और अन्य बनाम बलबीर सिंह (2004) 11 एससीसी 743:[2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 368; रवींद्र कुमार मिश्रा बनाम.

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड और एक अन्य (1987) पूरक एस. सी. सी. 739:[1988] एस. सी. आर. 501; पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी

मेडिकल साइंस एंड अदर (2002) 1 एस. सी. सी. 520:[2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 41-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2014 की सिविल अपील सं. 11871।

2002 के आर. एफ. ए. No.3765 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2014 की सिविल अपील सं. 11634।

रूप:

करण शर्मा, मोहित सिवाच, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

यादव नरेंद्र सिंह, जगदीश प्रसाद, मयंक कुमार सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. वर्तमान अपीलों में प्रत्यर्थी जसवंत सिंह को पंजाब पुलिस में सिपाही के रूप में भर्ती किया गया था।परिवीक्षा के दौरान, उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (इसके बाद संदर्भित) द्वारा सेवाओं से छुट्टी दे दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

पंजाब पुलिस नियम, 1934 (इसके बाद "पी. पी. आर". के रूप में संदर्भित) के नियम 12.21 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए। उसी को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी-वादी ने एक मुकदमे का नेतृत्व किया, जिसे आंशिक रूप से निचली अदालत द्वारा घोषित किया गया था और आरोपमुक्त करने के आदेश को इस आधार पर अवैध माना गया था कि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।

2. इसी पर जोर देते हुए, अपीलकर्ताओं/राज्य ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अमृतसर के समक्ष पहली अपील को प्राथमिकता दी। साथ ही, प्रतिवादी-वादी ने भी पहली अपील का नेतृत्व किया और इस आधार पर अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत मांगी कि चूंकि उसे सेवाओं से मुक्त करने का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं पाया गया था, इसलिए उसे कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए और सभी परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सामान्य निर्णय द्वारा राज्य के नेतृत्व में की गई अपील को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी-वादी की अपील को स्वीकार करते हुए उसे सभी सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार ठहराया।

3. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दो नियमित दूसरी अपीलों का नेतृत्व किया गया। पहला प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपनी अपील में फैसले के खिलाफ था और दूसरा प्रतिवादी-वादी को सभी सेवा लाभ प्रदान करने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के अनुदान के खिलाफ था। दोनों अपीलों को विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वर्तमान अपीलों का नेतृत्व किया गया है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी-वादी को परिवीक्षा पर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 12.11.1989 पर शामिल हुआ और उसे 1669 नंबर आवंटित किया गया था। उन्हें प्रशिक्षण के लिए 'पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र, जहां खेल, जिला होशियारपुर' (इसके बाद 'प्रशिक्षण केंद्र' के रूप में संदर्भित) भेजा गया था। इस बीच, उन्हें अन्य भर्ती कांस्टेबलों के साथ सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष कर्तव्य के लिए 24.11.1990 पर अमृतसर भेजा गया। उक्त कार्य के पूरा होने के बाद, ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त सभी सिपाहियों को मुक्त कर दिया गया और वे प्रत्यर्थी-वादी को छोड़कर प्रशिक्षण केंद्र को वापस रिपोर्ट कर दिए गए, जो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण केंद्र के पुलिस अधीक्षक (इसके बाद "एस. पी.". के रूप में संदर्भित) को इस तरह के आचरण के बारे में पता चला और एस. एस. पी. अमृतसर को दिनांक 21.02.1991 के ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया। इसमें कहा गया था कि बिना सूचना के लंबे समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के

कारण, प्रतिवादी-वादी को प्रशिक्षण में कोई रुचि नहीं थी, और उनमें जिम्मेदारी की भावना की कमी थी। इसलिए, यह 825

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जसवंत सिंह [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

सिफारिश की गई थी कि वह खुद को एक अच्छा, कुशल पुलिस अधिकारी साबित नहीं कर सकता है और वह अन्य प्रशिक्षुओं के लिए एक बुरी मिसाल कायम कर रहा है। एस. पी. ने प्रशिक्षण केंद्र की सूची से उनका नाम तत्काल प्रभाव से हटाने के अनुरोध के साथ पी. पी. आर. के नियम 12.21 के तहत सेवा से उनके निष्कासन की सिफारिश की, जिसमें अनुपस्थिति की अवधि को बिना वेतन के छुट्टी के रूप में माना गया। उक्त सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए, एस. एस. पी. ने प्रतिवादी-वादी को आरोपमुक्त करते हुए दिनांकित 28.03.1991 का आदेश पारित किया। उक्त आदेश प्रासंगिक है और तैयार संदर्भ के लिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“आदेश

सिपाही जसवंत सिंह सं. 1669/ए. एस. आर. पुत्र श्री हजार सिंह, जाति जाट, निवासी गाँव थोबा, पी. एस. रामदास, पुलिस जिला मजीठा को पी. पी. आर. 12.21 के तहत सेवा से छुट्टी दे दी गई है क्योंकि उनके पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है। 24.11.1990 से आज तक उनकी अनुपस्थित अवधि को गैर-शुल्क गैर-वेतन माना जाता है।

ओ. बी. में आदेश जारी करें।

एस. डी./- XXXXXXXXXX वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर

सं. 11369-76/बी दिनांकित 28.03.1991 "

5. प्रत्यर्ची-वादी ने आरोपमुक्त करने के आदेश से व्यथित होने के कारण, 1994 का दीवानी मुकदमा संख्या 306 का नेतृत्व करते हुए यह घोषणा करने की मांग की कि उक्त आदेश अवैध, असंवैधानिक, अमान्य है। उन्होंने अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के खिलाफ उन्हें सेवा में वापस लेने और उक्त अवधि के लिए उन्हें अर्जित वेतन और अन्य लाभों के बकाया प्रदान करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत के लिए भी प्रार्थना की। उनके द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने अत्यंत परिश्रम और कुशलता के साथ काम किया था। जब उन्हें विशेष ड्यूटी पर सुरक्षा गार्ड के रूप में अमृतसर भेजा गया, तो वे बीमार पड़ गए और उन्हें चिकित्सा उपचार कराना पड़ा, जिसके कारण वे समय पर ड्यूटी में शामिल नहीं हो सके। ठीक होने के बाद, जब उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अपने कर्तव्य में फिर से शामिल होने का प्रयास किया, तो उन्हें कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और बिना किसी कारण बताए उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई और सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त कार्रवाई को उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी।

[2023] 11 एस सी आर।

6. अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने इसकी रखरखाव और समय द्वारा वर्जित किए जाने के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए मुकदमे का विरोध किया। एस. पी., प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं होने के कारण, आवश्यक पक्ष के गैर-सहयोगी के बारे में भी आपत्ति ली गई थी। गुण-दोष पर, यह अनुरोध किया गया कि पी. पी. आर. के नियम 12.21 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्वहन का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है, और इसलिए, मुकदमे को खारिज कर दिया जाए।

7. सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अमृतसर ने दिनांक 12.01.2000 के फैसले के माध्यम से आंशिक रूप से यह आदेश देते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि, अपीलार्थियों-प्रतिवादियों द्वारा पारित आरोपमुक्त करने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को दो महीने के भीतर उक्त प्रक्रियात्मक अनियमितता को दूर करने और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिवादी-वादी के मामले का फैसला करने का निर्देश दिया।

8. उक्त निर्णय को अपीलार्थीगण द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि प्रतिवादी-वादी एक परिवीक्षाधीन सिपाही था और इसलिए, पीपीआर के नियम 12.21 के तहत शक्ति का उपयोग उसे कर्तव्य से मुक्त करने के लिए किया गया है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रावधानों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। साथ ही, अनिवार्य निषेधाज्ञा की गैर-मंजूरी के कारण, प्रतिवादी-वादी ने यह तर्क देते हुए अपील को भी प्राथमिकता दी कि चूंकि निर्वहन का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं पाया गया था, इसलिए उसे सभी परिणामी लाभ प्रदान करने वाले कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोनों अपीलों का निर्णय एक सामान्य निर्णय दिनांक 14.02.2002 द्वारा किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/राज्य के नेतृत्व में की गई अपील को खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादी-वादी के नेतृत्व में की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया और उसे उपार्जित सभी सेवा लाभों का हकदार ठहराया गया। हालांकि, अदालत ने अपीलार्थीगण को पीपीआर के नियम 16.24 के तहत प्रतिवादी-वादी के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की। उक्त निर्णय और डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा आम विवादित फैसले के माध्यम से स्वीकार किया गया था। इससे व्यथित होने के कारण, इन अपीलों को राज्य द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था और प्रशिक्षण के दौरान, उसे अन्य प्रशिक्षु/भर्ती कांस्टेबलों के साथ विशेष कर्तव्य के

लिए भेजा गया था।प्रतिनियुक्ति के पूरा होने के बाद, जबकि अन्य प्रशिक्षु सिपाहियों ने प्रशिक्षण 827 को वापस रिपोर्ट किया

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जसवंत सिंह [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 828

केंद्र और शामिल होने पर, प्रतिवादी-वादी ने न तो वापस रिपोर्ट की और न ही अपनी गैर-रिपोर्टिंग के लिए कोई सूचना दी।इसलिए, एस. पी., प्रशिक्षण केंद्र ने एस. एस. पी., अमृतसर को परिवीक्षाधीन सिपाही को छुट्टी देने के लिए पी. पी. आर. के नियम 12.21 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की सिफारिश की।उक्त सिफारिश में, यह संकेत दिया गया था कि बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण केंद्र में गैर-रिपोर्टिंग का कार्य प्रशिक्षण में रुचि और जिम्मेदारी की भावना की पूर्ण कमी को दर्शाता है।उक्त दृष्टिकोण में, एस. पी. ने आगे बताया कि प्रतिवादी-वादी खुद को एक अच्छा और कुशल पुलिस अधिकारी साबित नहीं कर सकता है।इसलिए, उक्त सिफारिश पर, एस. एस. पी. द्वारा नामांकन की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर नियम 12.21 पी. पी. आर. के तहत छुट्टी का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है क्योंकि परिवीक्षाधीन कांस्टेबल को प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित करने की संभावना नहीं पाई गई थी।यह भी आग्रह किया जाता है कि बर्खास्तगी का आदेश सरल है और दंडात्मक या कलंकित प्रकृति का नहीं है और उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले और डिक्री को लागू करते हुए कानून में गंभीर त्रुटि की है।उक्त दलीलों के समर्थन में, "पंजाब राज्य" के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है।

और अन्य बनाम सुखविंदर सिंह, (2005) 5 एस. सी. सी. 569 "और" पंजाब राज्य और अन्य बनाम कांस्टेबल अवतार सिंह, (2008) 7 एस. सी. सी. 405 "के मामले में निर्णय पर भी।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निर्वहन का विवादित आदेश सरल नहीं है, लेकिन यह दंडात्मक है।यह आग्रह किया जाता है कि एस. पी., प्रशिक्षण केंद्र द्वारा की गई सिफारिश इंगित करती है कि इस तरह की सिफारिश का आधार कदाचार के आरोप पर आधारित है।इसलिए, पी. पी. आर. के नियम 16.24 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच करना अनिवार्य था और उक्त कारण से, नीचे दिए गए न्यायालयों ने आरोपमुक्त करने के आदेश को उचित रूप से निर्धारित किया है।यह भी आग्रह किया जाता है कि समवर्ती निर्णय जैसा कि दर्ज किया गया है, इन अपीलों में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।उक्त तर्क के समर्थन में, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अमर कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

और अन्य, (2013) 4 पी. एल. जे. आर. 269 "और" रत्नेश कुमार चौधरी बनाम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार और अन्य, (2015) 15 एस. सी. सी. 151 "।

[2023] 11 एस सी आर।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, प्रत्यर्थी के खिलाफ पारित आदेश की प्रकृति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को पी. पी. आर. के नियम 12.21 के तहत सेवा से छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि अपीलार्थीगण की राय थी कि परिवीक्षाधीन कांस्टेबल के प्रभावी पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं थी। उक्त संदर्भ में, इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए, पी. पी. आर. के नियम 12.21 का संदर्भ प्रासंगिक है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“ 12.21 - एक सिपाही जिसे प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित करने की संभावना नहीं है, उसे अधीक्षक द्वारा नामांकन के तीन साल के भीतर किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है। इस नियम के तहत आरोपमुक्त करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।”

12. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने

शेर सिंह का मामला, पूर्व-आरक्षक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1994

एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 166 "ने पी. पी. आर. के नियमों 12.21, 19.3 और 19.5 की विषय-वस्तु और दायरे की विस्तार से जांच की है। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान कांस्टेबल निगरानी में रहता है और उसे कड़ी निगरानी में रखा जाता है। परिवीक्षाधीन को इस पद का कोई अधिकार नहीं है और उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन सेवा में अपना पद तभी सुरक्षित कर सकता है जब वह पुलिस अधीक्षक को आश्वस्त करे कि वह एक कुशल पुलिस अधिकारी के रूप में साबित होने की संभावना है। यह आगे कहा गया कि, यदि प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने पर, पुलिस अधीक्षक यह मानता है कि कोई विशेष कांस्टेबल सक्रिय, अनुशासित, आत्मनिर्भर, समयनिष्ठ, शांत, विनम्र, सीधा नहीं है या उसके पास उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के तकनीकी विवरणों का ज्ञान नहीं है, तो वह यथोचित रूप से यह राय बना सकता है कि उसके प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित होने की संभावना नहीं है। पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में, पुलिस अधीक्षक पीपीआर के नियम 12.21 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और कांस्टेबल को बल से मुक्त कर सकते हैं। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा सुखविंदर सिंह (उपरोक्त) के मामले में अनुमोदित किया गया है जिसमें यह कहा गया था कि यह न्यायालय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार से सहमत है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने फैसले पर भरोसा किया

पुलिस अधीक्षक बनाम द्वारका दास, (1979) 3 एस. सी. सी. 789

जिन पर पी. पी. आर. के नियम 12.21 और नियम 12.21 (3) पर भी विचार किया गया था, और 829

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जसवंत सिंह [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 830 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुलिस अधीक्षक के पास परिवीक्षा की अवधि के भीतर परिवीक्षाधीन को छुट्टी देने की शक्ति है।

13. पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुखबीर सिंह के मामले में,

(2004) 11 एस. सी. सी. 743 ", इस न्यायालय के पास पी. पी. आर. के नियम **12.21** पर विचार करने का अवसर था और पैराग्राफ **5,7** और **11** में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की -

"5. इस प्रकार, आरोपमुक्त करने का आदेश, प्रथम दृष्टया, दंडात्मक नहीं है, यह पंजाब पुलिस नियम 12.21 के संदर्भ में है, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि क्या वह घटना जिसके कारण उस आदेश को पारित किया गया था, उद्देश्य या प्रेरक कारक था या आरोपमुक्त करने के आदेश की नींव थी। 7. इस प्रकार यह सिद्धांत कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कदाचार समाप्ति के आदेश का उद्देश्य या आधार है, लागू किया जाने वाला परीक्षण यह सवाल पूछना है कि "जांच का उद्देश्य" क्या था। यदि कर्मचारी की ओर से किसी भी कदाचार को रोकने के उद्देश्य से कोई जांच या मूल्यांकन किया जाता है और इस कारण से उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, तो यह दंडात्मक प्रकृति का होगा। दूसरी ओर, यदि ऐसी जांच या मूल्यांकन का उद्देश्य किसी विशेष नौकरी के लिए किसी कर्मचारी की उपयुक्तता का निर्धारण करना है, तो ऐसी समाप्ति सरल होगी और दंडात्मक प्रकृति की नहीं होगी। यह सिद्धांत 1961 में उड़ीसा राज्य बनाम राम नारायण दास, (1961) 1 एस. सी. आर. 606 के मामले में शाह, जे. (जैसा कि वे तब थे) द्वारा निर्धारित किया गया था: ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 177: (1961) 1 एलएलजे 552। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी को "जांच के उद्देश्य या उद्देश्य" पर गौर करना चाहिए और केवल पूर्ववर्ती जांच के कारण समाप्ति को दंडात्मक नहीं मानना चाहिए। क्या यह (समाप्ति का आदेश) बर्खास्तगी के आदेश के बराबर है, यह जांच की प्रकृति, यदि कोई हो, तो उसमें की गई कार्यवाही और ऐसी जांच पर पारित किए गए आदेश के सार पर निर्भर करता है। उस मामले के तथ्यों पर, एक परिवीक्षाधीन की समाप्ति को बरकरार रखा गया था क्योंकि जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या कर्मचारी को आश्वस्त किया जा सकता है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं था कि क्या वह किसी कदाचार, लापरवाही, लापरवाही या अन्य अयोग्यता के लिए दोषी था।

11. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, अब हम यह निर्धारित करेंगे कि क्या, वास्तव में, वर्तमान मामले में निर्वहन का क्रम दंडात्मक प्रकृति का है। इस उद्देश्य के लिए, सबसे पहले, "जांच की प्रकृति" का पता लगाना आवश्यक होगा, यानी कि क्या समाप्ति पहले की गई है।

प्रत्यर्थी की ओर से कदाचार से जुड़े आरोपों की पूर्ण पैमाने पर औपचारिक जांच द्वारा, जिसकी परिणति अपराध के निवारण में हुई, और दूसरा, "जांच का उद्देश्य" अर्थात् क्या जांच का उद्देश्य कर्मचारी की ओर से किसी भी कदाचार का पता लगाना है या इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रत्यर्थी के प्रभावी पुलिस अधिकारी के रूप में साबित होने की संभावना नहीं है।"

14. इसी तरह, यह न्यायालय रवींद्र कुमार मिश्रा बनाम के मामले में है।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड और एक अन्य, **1987 (पूरक) एस. सी. सी. 739"** , एक अस्थायी कर्मचारी की समाप्ति के मामले को निपटाते समय, उद्देश्य और आधार के परीक्षण को लागू करते हुए सरल समाप्ति और दंडात्मक समाप्ति के बीच अंतर किया। इस न्यायालय ने उक्त भेद को स्पष्ट किया और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की -

"6. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, सेवा नियम जो लगभग समान हैं, वर्तमान अपील के निपटारे में इस न्यायालय के निर्णयों को प्रासंगिक बनाते हैं। इस न्यायालय की कई आधिकारिक घोषणाओं में, समाप्ति के आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए "उद्देश्य" और "आधार" की अवधारणा को लाया गया है। यदि अस्थायी सेवा में अधिकारी के अपराध को सेवा समाप्त करने के परिचालन उद्देश्य के रूप में लिया जाता है, तो आदेश को दंडात्मक नहीं माना जाता है, जबकि यदि समाप्ति का आदेश उस पर आधारित है, तो समाप्ति को एक दंडात्मक कार्रवाई माना जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि प्रत्येक नियोक्ता के लिए अस्थायी पदधारी की सेवा का आकलन करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसे अपनी नियुक्ति में शामिल किया जाना चाहिए या उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यह पता लगाना भी आवश्यक हो सकता है कि क्या अस्थायी आधार पर कुछ और समय के लिए आधिकारिक परीक्षण किया जाना चाहिए। चूंकि एक अस्थायी कर्मचारी या एक उच्च पद पर एक कार्यवाहक कर्मचारी दोनों के संबंध में ऐसा मूल्यांकन केवल इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि उपयुक्त प्राधिकारी एक मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने विचारों का रिकॉर्ड छोड़ देता है, इसलिए इस तरह के मूल्यांकन के बाद समाप्ति के आदेश को दंडात्मक बनाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। हमारे जैसे बड़े लोकतंत्र में, प्रशासन अवैयक्तिक होने के लिए बाध्य है और सार्वजनिक अधिकारियों के संबंध में, चाहे वह सरकारी हो या सार्वजनिक निगमों में, 831 के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन लिखित रूप में होना चाहिए।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जसवंत सिंह [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 832 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

रिकॉर्ड करें। हम नहीं समझते कि अपीलार्थी के इस तर्क में कोई औचित्य है कि एक बार ऐसा मूल्यांकन दर्ज हो जाने के बाद, उसके तुरंत बाद किए गए समाप्ति के आदेश को दंडात्मक रूप लेना चाहिए।”

15. इसी संदर्भ में, पवनेंद्र नारायण के मामले में यह न्यायालय

वर्मा बनाम संजय गांधी पीजीआई ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड अदर, (2002)

1 एस. सी. सी. 520 "ने परिवीक्षाधीन की समाप्ति के मामले में इसी सिद्धांत को दोहराया है। इसे इस प्रकार देखा गया है:

“29. हमारे समक्ष मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, प्रथम परीक्षण से संबंधित एक और, प्रतीत होने वाले जटिल, क्षेत्र को साफ़ करने की आवश्यकता है, अर्थात् समाप्ति क्रम में कौन सी भाषा कलंक के बराबर होगी? आम तौर पर, जब एक परिवीक्षाधीन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि परिवीक्षाधीन नौकरी के लिए अयोग्य है, चाहे वह दुराचार या अयोग्यता के कारण हो, समाप्ति आदेश में उपयोग की जाने वाली भाषा जो भी हो। हालांकि कड़ाई से बोलते हुए, कलंक समाप्ति में निहित है, एक साधारण समाप्ति कलंकित नहीं है। एक समाप्ति आदेश जो स्पष्ट रूप से बताता है कि परिवीक्षाधीन की नियुक्ति की समाप्ति के प्रत्येक क्रम में क्या निहित है, वह भी कलंकित नहीं है। पक्षों द्वारा उद्धृत और हमारे द्वारा पहले उल्लिखित निर्णय भी ऐसा नहीं मानते हैं। एक कलंक के रूप में राशि के लिए, आदेश एक ऐसी भाषा में होना चाहिए जो नौकरी के लिए केवल अनुपयुक्तता के अलावा कुछ लागू करता है।”

16. समान मुद्दे पर विभिन्न घोषणाओं पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने सुखविंदर सिंह (ऊपर) के मामले में पैराग्राफ 20 में इस प्रकार टिप्पणी की:

“20. वर्तमान मामले में न तो कोई औपचारिक विभागीय जांच की गई थी और न ही कोई प्रारंभिक तथ्यात्मक जांच की गई थी और आरोपमुक्त करने का एक साधारण आदेश पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने लिखित बयान में दिए गए एक बयान के आधार पर एक इमारत का निर्माण किया है कि प्रत्यर्थी अपनी सेवा की छोटी अवधि के दौरान आदतन अनुपस्थित था और उससे यह निष्कर्ष निकाला है कि यह कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति थी जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिमाग में भारी पड़ी क्योंकि कर्तव्य से अनुपस्थिति एक कदाचार है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि प्रत्यर्थी को सेवा से छुट्टी देने के आदेश और कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति के बीच सीधा संबंध है और इसलिए, उसे सेवा से छुट्टी देने के आदेश को दंडात्मक प्रकृति के रूप में देखा जाएगा।

नियमों के नियम 16.24 के तहत नियमित जांच का आह्वान करना। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में पूरी तरह से गलत किया है कि दिनांक 1 का आरोपमुक्त करने का आदेश वास्तव में कदाचार पर आधारित था और इसलिए दंडात्मक

प्रकृति का था, जिससे पहले एक नियमित विभागीय जांच होनी चाहिए थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रत्यर्थी लगभग आठ महीने पहले नियुक्त होने के कारण परिवीक्षा पर था। जैसा कि अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1983) 2 एस. सी. सी. 217 में देखा गया है: 1983 एससीसी (एल एंड एस) 303: ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 494] परिवीक्षा की अवधि नियोक्ता को नौकर के काम, क्षमता, प्रभावशीलता, ईमानदारी और क्षमता को देखने के लिए समय और अवसर देती है और यदि वह पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्वामी को निर्धारित अवधि के दौरान या अंत में बिना किसी अधिक के अपनी सेवा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे परिवीक्षा की अवधि के रूप में वर्णित किया गया है। केवल प्रारंभिक जांच के आयोजन में जहां एक कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, निर्वहन या सेवा की समाप्ति के एक अन्यथा हानिरहित आदेश को दंडात्मक प्रकृति का नहीं बना देगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि कर्तव्य से प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति आदेश की नींव थी, जिसके कारण नियमों के नियम 16.24 (ix) के तहत परिकल्पित जांच की आवश्यकता थी।”

17. उक्त निर्णय के बाद इस न्यायालय ने अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 में इस प्रकार टिप्पणी की है:

“11. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हम पंजाब राज्य के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील से पूरी तरह सहमत हैं कि इस मामले में शामिल विवाद अब एकीकृत नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने पृथ्वीपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2002) 10 एस. सी. सी. 133 में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था: 2003 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 103]। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब कलंक हो जाता है, तो सिद्धांत अच्छी तरह से तय हो जाता है, कोई भी आदेश पारित करने से पहले एक अवसर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि जहां निर्वहन का आदेश हानिरहित लगता है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर, पर्दे के पीछे देखने पर अगर कदाचार की कोई सामग्री मौजूद है और जो निर्वहन के आदेश को पारित करने का आधार है, या ऐसा उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई परिणामी आदेश, यहां तक कि निर्वहन का भी, 833 के रूप में माना जाएगा।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जसवंत सिंह [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 834

कलंकित। सुखविंदर सिंह [(2005) 5 एस. सी. सी. 569 में निर्णय: 2005 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 705] तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था और 2005 में उस निर्णय को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए अलग दृष्टिकोण रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम उक्त निर्णय से पूरी तरह से बंधे हैं।”

18. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में दोहराए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम मामले के तथ्यों की जांच करते हैं जो आरोपमुक्त करने के आदेश की ओर ले जाते हैं,

तो यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-वादी को एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और परिवीक्षा पर 12.11.1989 पर कर्तव्यों में शामिल हो गया था। परिवीक्षा के दौरान, जब वे प्रशिक्षण पर थे, उन्हें अन्य प्रशिक्षु सिपाहियों के साथ अमृतसर जिले में 24.11.1990 पर कानून और व्यवस्था की झूटी के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी-वादी और अन्य रंगरूटों को उक्त कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया और प्रत्यर्थी-वादी को छोड़कर प्रशिक्षण केंद्र में वापस रिपोर्ट किया गया, जो प्रशिक्षण केंद्र को बिना किसी सूचना के लंबे समय तक अनुपस्थित रहे। एस. पी., प्रशिक्षण केंद्र ने दिनांक 21.02.1991 के ज्ञापन के माध्यम से एस. एस. पी. को एक सिफारिश की कि प्रतिवादी-वादी ने प्रशिक्षण में कोई रुचि नहीं दिखाई है और जिम्मेदारी की भावना का अभाव है, आगे यह सिफारिश करते हुए कि वह खुद को एक अच्छे और प्रभावी पुलिस अधिकारी के रूप में साबित करने की संभावना नहीं है, इसलिए उसे पी. पी. आर. के नियम 12.21 के तहत छुट्टी दी जा सकती है। उक्त नियम के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन सिपाही के प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित होने की संभावना नहीं पाई जाती है, तो उसे नामांकन की तारीख से तीन साल के भीतर किसी भी समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपमुक्त किया जा सकता है। एस. एस. पी. ने पर्यवेक्षण अधिकारी (एस. पी., प्रशिक्षण केंद्र) की सिफारिश पर भरोसा करते हुए एक राय बनाई कि परिवीक्षाधीन कांस्टेबल को उसके आचरण के कारण एक प्रभावी पुलिस अधिकारी साबित करने की संभावना नहीं है जैसा कि ऊपर बताया गया है और चर्चा की गई है।

19. हमारे सुविचारित विचार में, तीनों न्यायालयों ने पी. पी. आर. के नियम 12.21 का गलत अर्थ निकाला और प्रतिवादी-वादी के नेतृत्व में मुकदमे का फैसला सुनाया। निष्कासन के आदेश की सामग्री को देखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आदेश में कथित कदाचार का कोई आधार नहीं है और यह एक परिवीक्षाधीन कांस्टेबल के सरल निर्वहन का आदेश है। द.

रत्नेश कुमार चौधरी (ऊपर) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया

प्रत्यर्थी द्वारा इस साधारण कारण से कोई मदद नहीं की जाती है कि उस मामले में, प्रारंभिक नियुक्ति को एक सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर अवैध बताया गया था जो रिकॉर्ड में थी। इसके बाद, उक्त सतर्कता रिपोर्ट के विवरण पर नोटिस जारी किया गया जिसमें गंभीर आरोप थे और उक्त में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

विचित्र स्थिति, न्यायालय ने पाया कि समाप्ति सरल नहीं थी, लेकिन यह दंडात्मक थी

20. इसी तरह, अमर कुमार (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें अदालत ने पाया कि उसमें अपीलार्थी ने हंगामा/आंदोलन/विरोध करने के लिए उकसाया था और प्रशिक्षुओं में से एक की

मृत्यु के संबंध में झूठी अफवाहें फैलाकर नारे भी लगाए थे, जो बर्खास्तगी का आदेश पारित करने का आधार था। इस प्रकार, उक्त मामले में, न्यायालय की राय थी कि समाप्ति का आदेश सरल नहीं हो सकता है। ऊपर उल्लिखित दोनों मामलों में, गंभीर कदाचार का आरोप आम है, तत्काल मामले के विपरीत, जिसमें आरोपमुक्त करने का आधार किसी गंभीर आरोप या कदाचार के कार्य पर नहीं है। बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण प्रशिक्षण केंद्र के संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण की सिफारिश पर छुट्टी का आदेश पारित किया गया था। प्राधिकरण ने पाया कि परिवीक्षाधीन कांस्टेबल को प्रशिक्षण में कोई रुचि नहीं है, और न ही जिम्मेदारी की कोई भावना है, इसलिए, वह खुद को एक अच्छा, कुशल पुलिस अधिकारी साबित नहीं कर सकता है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, दोनों संदर्भित मामले तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं।

21. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय और नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में पूरी तरह से गलत है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए। तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है, और प्रतिवादी-वादी के नेतृत्व में मुकदमा खारिज हो जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन